SAP स्थिर रखकर UP सरकार ने दी शुगर मिलों को बड़ी राहत

[मनमोहन राय | लखनऊ]

चीनी मिलों को राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार तीसरे साल भी गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी नहीं की। राज्य सरकार ने 2014-15 पेराई सीजन के लिए गन्ने के समर्थन मूल्य में कोई फेरबदल नहीं किया है। पिछले काफी समय से राज्य की चीनी मिलें और गन्ना किसान समर्थन मूल्य को लेकर लॉबीइंग करते रहे हैं।

अखिलेश यादव सरकार ने 2014-15 पेराई सीजन के लिए गन्ने के कॉमन वेरायटी का समर्थन मूल्य (एसएपी) 280 रुपये प्रति क्विंटल पर बनाए रखा है। अर्ली वेरायटी की कीमत जहां 290 रुपये प्रति क्विंटल है वहीं रिजेक्टेड वेरायटी की कीमत प्रति क्विंटल 275 रुपये होगी।

राज्य के प्रधान सचिव प्रदीप भटनागर ने कहा कि सरकार के लिए किसानों का हित सबसे ऊपर है, लेकिन हकीकत यह है कि बाजार में चीनी की कीमत स्टेबल बनी हुई है। इसलिए समर्थन मूल्य तय करते वक्त इन बातों का भी ख्याल रखा जाना जरूरी था। शुगर मिलें गन्ने का समर्थन मूल्य घटाकर 225 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग कर रही थीं। उनका कहना था कि अगर गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई तो उनकी

वित्तीय हालत बिगड़ जाएगी। वहीं किसान गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 320-325 रुपये किए जाने की मांग कर रहे थे।

गन्ना किसानों के नेता सुधीर पंवार ने कहा, 'गन्ने का समर्थन मूल्य 280 रुपये प्रति क्विंटल रखे जाने से किसानों के हितों को नुकसान होगा। महंगाई और इनपुट कॉस्ट में हुई वृद्धि को देखते हुए इसे बढ़ाकर करीब 320 रुपये प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए था।' उन्होंने कहा, 'समर्थन मूल्य को लेकर सरकार के फैसले से लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री को नुकसान होगा और इस साल गन्ने के रकबे में भारी गिरावट आएगी। इससे चीनी उत्पादन के मामले में राज्य की लीडरशिप पोजीशन को झटका लगेगा।'

चीनी मिलों ने सरकार को लेटर लिखकर पेराई सीजन रोके जाने की धमकी दी थी। हालांकि सरकार ने इस मामले में सख्ती दिखाई क्योंकि चीनी मिलों के इस फैसले से करीब 35 लाख गन्ना किसानों के परिवारों पर सीधा असर पड़ता। राजनीतिक दलों के लिए गन्ना किसान बड़े वोट बैंक है, जिन्हें नाराज करने का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता।

सरकार की सख्ती के बाद महीने की शुरुआत में चीनी मिलों के तेवर थोड़े नरम हुए। हालांकि गन्ने के समर्थन मूल्य में कटौती नहीं किए जाने और समय पर भुगतान किए जाने की सख्ती को देखते हुए चीनी मिलों ने अभी तक पेराई सीजन शुरू किए जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन और इसकी उत्तर प्रदेश इकाई ने इस मामले में कोई टिप्पणी देने से मना कर दिया। गुरुवार को दिल्ली में चीनी मिल मालिकों की बैठक होनी है। बैठक के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि वह पिछले साल की तरह क्या इस बार भी राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

Economonic times

14/11/14